भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1827**
10 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ

**विषय: ओडिशा में किसानों के लिए सहायता**

**1827. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केंद्रीय बजट ने ओडिशा में सिंचाई, श्री अन्न, एफपीओ और जलवायु-अनुकूल कृषि के लिए सहायता को सुदृढ़ किया है;
(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पीएम-किसान, पीएमएफबीवाई और आरकेवीवाई के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है; और
(ग) ये उपाय लघु और जनजातीय किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दे रहे हैं?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ग): भारत सरकार ओडिशा सहित पूरे देश में सिंचाई, मिलेट्स, एफपीओ और जलवायु-अनुकूल कृषि को अधिकाधिक सहायता देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों की एक व्यापक श्रृंखला कार्यान्वित कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा ओडिशा सहित पूरे देश में कार्यान्वित की गई स्कीमों की सूची **अनुबंध-I** पर है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम के तहत, 19 नवंबर 2025 को जारी 21वीं किस्त के दौरान कुल 34,15,469 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। अब तक 21 किस्तों के माध्यम से 13,801.99 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 में क्रमशः 141.6 लाख और 146.8 लाख किसानों को लाभ प्राप्त हुआ।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) एक व्यापक स्कीम है जिसमें व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख स्कीमें और परियोजना आधारित घटक शामिल हैं। लाभार्थियों का विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

निम्नलिखित से यह स्पष्ट है कि ये स्कीमें ओडिशा सहित पूरे देश के छोटे और आदिवासी किसानों की आय बढ़ाने में योगदान दे रही हैं:

• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की स्कीमों के समन्वय से अपनी आय में दो गुना से अधिक वृद्धि की है।
• सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें चरण (जनवरी 2019-दिसंबर 2019) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई 2018-जून 2019 के कृषि वर्ष के संदर्भ में कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया। इस सर्वेक्षण के अनुसार, प्रति कृषि परिवार अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 70वां चरण) में ₹6,426 से बढ़कर वर्ष 2018-19 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 77वां चरण) में ₹10,218 हो गई।

• घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्न प्रकार है:

| क्षेत्र | विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रु.) | |
|---|---|---|
| | 2011-12 एनएसएस (68$^{वां}$ दौर) | 2023-24 |
| ग्रामीण | 1,430 | 4,122 |
| शहरी | 2,630 | 6,996 |
| ग्रामीण एमपीसीई के प्रतिशत के रूप में अंतर | 83.9 | 69.7 |

**अनुबंध।**

कृषि क्षेत्र में राज्यों को सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित स्कीमों की सूची

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
13. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
14. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
20. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
29. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

*****